

(घ) क्या मूंगफली के कम और घटिया किस्म के उत्पादन के कारण किसानों में व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिए सरकार सीतापुर (उत्तर प्रदेश) में कोई अनुसंधान संस्थान खोलना आवश्यक समझती है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) वर्ष 1982-83 के दौरान राज्यों में मूंगफली उत्पादन के अंतिम आकलन अभी उपलब्ध नहीं हैं। अगत वर्ष की तुलना में 1982-83 के मौसम में सीतापुर मंडी में मूंगफली की आमद में कुछ कमी आई। प्रारंभिक आकलन के अनुसार, कुछ राज्यों ने खरीफ 1982 में मूंगफली के अन्तर्गत बुआई क्षेत्र में कमी होने की रिपोर्ट दी है।

(ग) मूंगफली की उन्नत किस्में विकसित करने के लिये अनुसंधान के प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खेती के लिए एक उन्नत किस्म "चन्द्रा" पहचानी गई है जो उपलब्ध स्थानीय किस्मों से पैदावार में श्रेष्ठ है।

(घ) और (ङ) तिलहन में सुधार करने के लिये अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में एक केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहा है जहां उन्नत किस्मों तथा प्रबन्ध प्रौद्योगिकी को विकसित करने और कीट कृमियों के नियंत्रण पर अनुसंधान किया जाता है। सीतापुर में अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चीनी का उत्पादन

94. श्री रामावतार शास्त्री : क्या

द्यतया नागरिक पूर्ति मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 का देश में चीनी के उत्पादन का व्यौरा क्या है ;

(ख) इस समय देश में चीनी के भंडार की स्थिति क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार चीनी के भंडार को देखते हुए चीनी के मूल्य कम करने का है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) वर्ष 1983-84 के दौरान चीनी के उत्पादन को बढ़ाने की सरकार की क्या योजना है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 1982-83 मौसम के दौरान देश में 31 जनवरी तक चीनी का उत्पादन 32.76 लाख मीटरी टन के स्तर तक पहुंच गया है। अनुमान है कि उक्त मौसम के दौरान चीनी का कुल उत्पादन लगभग 80 लाख मीटरी टन होगा।

(ख) चीनी फैक्ट्रियों के पास 31-1-1983 तक लगभग 41.71 लाख मीटरी टन चीनी का स्टाक था।

(ग) और (घ). दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की प्रमुख मंडियों में जनवरी, 1982 के प्रथम सप्ताह में चीनी के थोक मूल्य 580 रुपये से 533 रुपये प्रति क्विंटल के बीच चल रहे थे। आन्तरिक खपत के लिए

मुक्त बिजली की चीनी की उदारतापूर्वक निर्मुक्तियां करने से चीनी के मूल्यों में निरन्तर गिरावट आ रही थी और 10-2-1983 को चीनी के थोक मूल्य 409 रुपये से 458 रुपये प्रति क्विंटल के रेंज में चल रहे थे। क्योंकि चीनी फैक्ट्रियों से गन्ना उत्पादकों को गन्ने का लाभकारी मूल्य देने की अपेक्षा की जाती है, इसलिए चीनी मूल्यों में कोई अनुचित कमी करना वांछनीय नहीं समझा जाता है।

(ड) आगामी वर्षों में चीनी का पर्याप्त उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार चीनी फैक्ट्रियों द्वारा किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य का भुगतान करवाना सुनिश्चित कर रही है। बफर स्टॉक तैयार करने, बैंक मार्जिन को कम करने आदि जैसे अन्य उपाय करने से भी उद्योग भविष्य में अधिक स्तर तक उत्पादन करने में सक्षम होगा जिसके फलस्वरूप गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्यों का भुगतान हो पाएगा।

Rajasthan Canal Project

95. SHRI DAULAT RAM SARAN: Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) the overall delay (till date) in the execution of the Rajasthan Canal project and to what extent its cost has escalated as a result thereof; and

(b) what are the major factors responsible for the continuous and frequent re-scheduling of the completion programme of the project and what is the present position with regard to its completion?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) As per 1970 project estimates, the project in its present form was scheduled to be completed by 1980-81. It is now proposed to be substantially completed by 1984-85. The cost of the project as per 1970 estimates was Rs. 207 crores and its latest estimate is likely to be Rs. 534.5 crores.

(b) The rescheduling of the project was necessary on account of inadequate allocation of funds by the State during initial years.

As per present programme the main canal almost in all respects and distribution channels mostly unlined are scheduled to be completed by March 1985. The remaining work of completion and lining of distributaries will spillover to the Seventh Plan.

Irrigation Schemes in Gujarat for 1982-83

96. SHRI MOTIBHAI R. CHAUDHARI: Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) the number of irrigation schemes submitted by the Government of Gujarat for the year 1982-83;

(b) the details of the schemes approved by Government; and

(c) financial assistance given to the State for the completion of these schemes?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) During the year 1982-83, two irrigation schemes have been submitted by the Government of Gujarat for technical examination in the Central Water Commission and approval by the Planning Commission.